statistical base of the Ninth Five Year Plan which will be placed before National Development Council shortly; and

(c) if so, what was the compulsion for changing the base year just at this juncture?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI RAM NAIK): (a) Yes, Sir.

(b) Changes in the base year of calculation of macro-economic aggregates do not materially affect the calculations of the Five Year Plan since the macro-economic balances continue to be maintained. As a result, the parametric estimates can be suitably adjusted to take into account the adjustment in the base.

(c) Change of base year of the National Accounts Statistics is a regular periodic exercise to provide the correct picture of the economy.

**Implementation of Developmental Schemes under MPLADS**

*53. SHRI GAYA SINGH:
SHRI GURUDAS DAS GUPTA:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the implementation of various development works under the MPs Local Area Development Scheme (MPLADS) has been very tardy in different States;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the main reasons therefor and remedial steps, if any being taken?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI RAM NAIK): (a) to (c) Some complaints of delay in implementation of works under MPLADS have been received. Some reasons for slow progress are : application of Model Code of Conduct during Elections of the Parliament, State Legislatures and Panchayati Raj Institutions, late receipt of recommendations from MPs, change in recommendation by MPs, non-availability of land etc. All the State Governments/UTs have been requested to issue instructions to all the concerned for prompt action and implementation of MPLADS works in accordance with the revised guidelines and also to ensure monitoring, supervision, coordination as outlined in these guidelines. All the District Collectors have also been asked to stipulate a time limit for the implementing agencies to complete the given work in a specific time frame depending upon nature of work and to take action against the implementing agencies in case of failure.

Inter-action meetings between the M.P.s and implementing officers like District Collectors have also been held on state level for some states.

**Restriction on entry of Hong Kong**

*54. SHRI S.M. KRISHNA: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the news-item captioned "Hon Kong restricts Indians entry; visa needed for stay for over two weeks" that appeared in the *Times of India* dated the 19th Januanry, 1999;

(b) if so, the Government's reaction thereto; and

(c) the details of the new procedure adopted in that regard and remedy, if any, suggested?

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI JASWANT SINGH): (a) to (c) Yes Sir, Government's attention have been drawn to the news-item referred to in the question.

The HKSAR Government has decided that, effective from January 18, 1999, holders of Indian passports may enter Hong Kong without visa for a period of not more than 14 days instead of 3 months as per the existing policy. For a stay of over 14 days, Indian nationals will now have to obtain visa from Chinese Embassy or Consulate in the country of origin, or, through the Hong Kong Immigration Department, before arrival.

We have conveyed our regret to the concerned authorities in China and the Hong Kong Special Administrative Region at the revision of the visa privileges for Indian passport holders visiting Hong Kong. We have requested that the earlier visa policy for Indian nationals be restored. We have pointed out that this move would adversely affect the Indian visitors (over nintey-three thousand in 1998) to Hong Kong and the smooth development of our bilateral trade which is in excess of US $ 2.5 billion.

### प्रशासनिक सेवाओं की जवाबदेही

*55. **श्री नरेन्द्र मोहन:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत की प्रशासनिक सेवाओं में और अधिक जवाबदेही लाने के लिए कोई व्यवस्था की गई है; और

(ख) क्या न्यायपालिका अथवा अन्य प्रमुख संस्थाओं ने इस संबंध में सरकार का ध्यान आकर्षित किया है?

**कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व और बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादाम्बूर एम० आर० जनार्दनन):** (क) प्रशासनिक सेवाओं में जवाबदेही लाने के बारे में केन्द्रीय सचिवालय कार्यालय पद्धति नियम-पुस्तिका में विभिन्न प्रावधान किये गये हैं। इन प्रावधानों में उस स्थिति में निपटान के स्तर और मामले को प्रस्तुत करने संबंधी चैनल का वर्णन किया गया है जब मौखिक विचार-विमर्श, उच्च अधिकारियों द्वारा दिये गये मौखिक अनुदेशों अथवा मंत्री जी से या उनकी ओर से दिये गये मौखिक आदेशों के संबंध में सामान्य कार्य-पद्धति अथवा नियमों और प्रक्रियाओं से विचलन करना पड़ जाता है। प्रशासनिक सेवाओं में अधिक जवाबदेही लाने की दृष्टि से वर्ष 1986-87 से कार्य-कलापों के कैलेन्डर के रूप में एक वार्षिक कार्य योजना प्रणाली लागू है जिसमें तिमाही-वार लक्ष्यों के साथ-साथ ऐसे कार्यों एवं उद्देश्यों को निर्दिष्ट किया जाना होता है जिन्हें अधिकारियों/प्रभागों/अनुभागों आदि द्वारा हासिल किया जाता है। इन लक्ष्यों की प्राप्ति पर तिमाही/अर्द्धवार्षिक आधार पर निगरानी रखी जाती है। सरकारी कर्मचारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में उपयुक्त परिवर्तन किये गए हैं ताकि पूर्व-निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में उनकी उपलब्धियों का वास्तविक मूल्यांकन किया जा सके। कर्मचारियों को अपने कार्य-निष्पादन में सत्यनिष्ठा और जवाबदेही को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न सेवाओं की आचरण नियमावली में भी प्रावधान किये गए हैं।

प्रभावी और उत्तरदायी प्रशासन के संबंध में सरकार की कार्य योजना तैयार किये जाने के फलस्वरूप, लोक सेवाओं के अनेक क्षेत्रों में ऐसे मानक निर्धारित करते हुए नागरिक चार्टर तैयार किये गये हैं जिनकी जनता द्वारा इस प्रकार की सेवाओं की आशा की जा सकती है। इन चार्टरों के द्वारा प्रशासनिक सेवाओं को जनता के प्रति अधिक जवाबदेही बनाने का प्रयास किया गया है।

(ख) उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में हुए विलंब से संबंधित विशेष अनुमति याचिका में एक मामला सं० 1996 का 3337 [जे टी 1997(2) एस सी 463] निबटा रहा था। उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी को रिट याची के मामले पर विचार करने और तर्कसम्मत आदेश द्वारा उसे दो महीने के भीतर निबटाने का निदेश दिया था। न तो उक्त निदेश का अनुपालन किया गया न ही प्रतिवादी ने उक्त निदेश के अनुपालन के क्रम में समय बढ़ाए जाने की मांग की। उच्चतम न्यायालय ने उपर्युक्त आदेश का अनुपालन न किए जाने के कारण व्यक्तिगत रूप से प्रतिवादी के विरुद्ध (वाद) खर्च की शास्ति लगाई। इसी संदर्भ में ही उच्चतम न्यायालय ने, न्यायालय के प्रति नौकरशाही की जवाबदेही के बारे में टिप्पणी की। उक्त निर्णय से प्रतीत होता है कि न्यायालय की यह मंशा थी कि न्यायालय के निदेशों का तुरंत अनुपालन किया जाना अपेक्षित है और